

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 22, बुधवार, शके 1945-अप्रैल 12, 2023 Chaitra 22, Wednesday, Saka 1945- April 12, 2023	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2023

जी.एस.आर.08 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (क) के विद्यमान परन्तुक (vi) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(vii) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो कांस्टेबल भर्ती, 2018 में, मेवाड़ भील कोर बांसवाड़ा और 10 वीं बटालियन आरएसी बीकानेर में चयनित हो गये थे किंतु उधमपुर में मूल प्रशिक्षण और सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड में कांस्टेबल के पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिये गये थे और जो सेवा से हटा दिये गये थे, ऐसे व्यक्ति डी.बी. विशेष अपील रिट सं.515/2021, राजस्थान राज्य और अन्य बनाम पीयूष पाटीदार और अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, के निर्णय दिनांक 04.01.2022 की अनुपालना में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किये जायेंगे, यदि अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक पद के लिए इन नियमों के अधीन विहित की गयी शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य शर्तें पूर्ण करते हों। किन्तु नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कंप्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर इन नियमों में यथाविहित कोई एक कंप्यूटर

अर्हता में से कोई एक अर्जित करनी होगी, जिसमें विफल होने पर उसकी परिवीक्षा की कालावधि बढ़ायी गयी मानी जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसका कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त न कर दे;

- (ख) नियुक्ति के समय, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कंप्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु अभ्यर्थियों से ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या किसी एक भाषा या तो अंग्रेजी या हिंदी में कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा दो वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल नहीं की जाती है, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने की दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई भी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धियां नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

वह कालावधि जिसके लिए कर्मचारी सेवा से बाहर रहा था उसे असाधारण छुट्टी की मंजूरी द्वारा विनियमित किया जायेगा, जो किसी भी प्रयोजन के लिए संगणित नहीं की जायेगी।”

3. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुक (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

- “(ix) यह कि नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के परन्तुक (vii) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए तैयार की गयी योग्यता सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी। ये व्यक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारम्भ से पूर्व नियमित रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों से रैंक में कनिष्ठ होंगे।”

[सं.एफ.3(4)डीओपी/ए- II/2022]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।